

**श्री बसंत साठे :** नागपुर का यहत्व चितना मेरे विक्र जानते हैं, उतना मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं वहां से आता हूँ। इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि ये दोनों सिस्टम—माइक्रोबेच और “इनसेट”—को मिलाकर नागपुर के लिए विचार किया जाएगा। जबकि मैं यदि कोई दिक्कत आए और आपके प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार उसमें कुछ योगदान करे, तूकि नागपुर भी राजधानी है, तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

**प्रो० निमंला कुमारी शक्ताचत :** अध्यक्ष महोदय . . .

**अध्यक्ष महोदय :** निमंला जी, इस सवाल का तो बहुत लिमिटेड रेंज है।

**प्रो० निमंला कुमारी शक्ताचत :** मैं यह पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान में कोटा एक औद्योगिक नगर है और चितौड़गढ़ एक ऐतिहासिक नगर है—क्या इन नगरों में दूरदर्शन की कोई व्यवस्था करने का सरकार का विचार है?

**अध्यक्ष महोदय :** यह राजस्थान का सवाल नहीं है, फिर भी मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहूँ तो दे सकते हैं।

**श्री बसंत साठे :** राजस्थान में जयपुर में व्यवस्था है। आगे की योजना में अजमेर के लिये विचार किया जा रहा है।

**श्री सुन्दर सिंह :** स्पीकर साहब . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** चौधरी साहब, इस-दे-विच पंजाब दी गल नहीं निकलती है।

**श्री सुन्दर सिंह :** टी०वी० से पंजाब का सत्यानाश हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं . . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** तुसी-बह-आओ।

This concern Nagpur.

What is there more to ask about it?  
Let us proceed to the next question.

### Gujarat State Fertilizer Company

+  
**\*839. SHRI AMARSINH RATHAWA:**

**SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:**

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Gujarat State Fertilizer Company is facing shut-down;

(b) if so, what are the main reasons; and

(c) what measures are being taken to save it from closure?

**THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL):** (a) The sale of caprolactam, one of the products produced by Gujarat State Fertiliser Company has been poor during the last few months.

(b) The selling price of caprolactam of GSFC is higher than the landed price of imported caprolactam. Furthermore, the quality of caprolactam produced by GSFC is inferior and unacceptable for some of the industrial uses.

(c) GSFC has been advised to reduce their selling price to a level which will still provide it a fair return on capital. At the reduced prices the user industry will prefer GSFC material and the benefit of lower price will ultimately be available to the consumer.

**श्री अमर सिंह राठवा :** माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि वहां का कैप्रोलैक्टम बिट्या है मैं जानना चाहता हूँ कि इस का कारण क्या है? 1972 में सरकार इस कम्पनी में 51 प्रतिशत शेयर रखना चाहती थी और भाज भी रखना चाहती है—वे जानना चाहता हूँ कि अगर 51 प्रतिशत शेयर नहीं रखा है तो उस का क्या कारण है?

**श्री बोरेन्ड्रा पाटिल :** इस में गवर्नरमेंट का भी शेयर है और माइक्रोबेच कम्पनियों का भी शेयर है, इसलिये शेयर न रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

**श्री अमर चिह्न राठोड़ा :** गवर्नेंट का बेवर तो है, लेकिन 51 परसेन्ट नहीं रहा है—ऐसा मेरा स्थान है। मेरा प्रश्न है—इस कम्पनी के जो चेयरमैन हैं, वे गुजरात के सब से बड़े उद्योगपति रहे हैं, उन को बदला नहीं जा रहा है—इस का क्या कारण है? चूंकि एक उद्योगपति इस का चेयरमैन है, इसलिए इस में जल्द गड़बड़ होती होगी।

**श्री शीरेन्द्र पाटिल :** चेयरमैन कौन होगा, मैनेजिंग डाइरेक्टर कौन होगा—जहां तक मुझे मालूम है, उन को गवर्नेंट एप्लाइट करती है।

जो चेयरमैन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं या जो मैनेजिंग डाइरेक्टर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उन को निकालने का पूरा अधिकार गवर्नेंट को है लेकिन सबाल यहां पर यह नहीं है। सबाल तो माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि गुजरात स्टेट फिल्म्स इंजिनियर कम्पनी जो केप्रोलेक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है, उस के लिए मार्केट नहीं है, 5 हजार टन के प्रोलेक्टर्स उन के यहां पड़ा हुआ है और उस को कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए यह क्राइसिस वहां पैदा हुआ है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा था, उस का जवाब मैंने दे दिया है।

**श्री बालासाहित चिह्ने पाटिल :** अभी मिनिस्टर साहब ने चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर के बारे में बताया कि भगवर वे ठीक काम नहीं करते हैं तो उन को निकाला जा सकता है लेकिन मंत्री जी ने आपने देव्हाई में बताया है कि इस कम्पनी का जो केप्रोलेक्टर्स है, वह ऊंची ब्यालिटी का नहीं है और जो आयातित केप्रोलेक्टर्स की लैंडड कास्ट है, उस से वह महगा है। तो फिर जो चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर उन्होंने एप्लाइट किये हैं, वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आपने उत्तर में इन्होंने यह बताई है कि कास्ट को रिड्यूस करने के लिये इन्होंने कहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कैफियत इस कम्पनी में एम्प्लाय किया गया है, उस का ठीक रिटर्न मिले और जो चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर गवर्नेंट ने एप्लाइट किये हैं, वे डिस्ट्रिक्शनरी प्राइस तय कर देते हैं जिस की वजह से यह जो स्टेट अन्डरटेकिंग है, इस में यह सब घाटा होता है तो इस के माइने यह होते हैं कि आम लोगों ने विश्वास के पात्र नहीं होते। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे कोई विचार नहीं कर रही है, जिस दृंग से स्टेट अन्डरटेकिंग चलनी चाहिये, उन को दैसे चलाने के लिए क्या आप तुल सोच रहे हैं या नहीं।

**श्री शीरेन्द्र पाटिल :** माननीय सदस्य का जो यह अधिप्राय है कि स्टेट फिल्म्स इंजिनियर कम्पनी धाटों में चल रही है, यह बात नहीं है। मुझे देखा जाए तो जो केप्रोलेक्टर्स पैदा होता है, गुजरात स्टेट फिल्म्स जर कम्पनी में उस का काफी भावा में प्रोडक्शन होता है और उस की कैपेसिटी 20 हजार टन के प्रोलेक्टर्स पैदा करने की है और वह काफी मुनाफा भी है उस को काफी प्रोफिट हो रहा है। 1977 में फिल्म की कीमत 15600 रुपये टन थी जिस को बढ़ा कर उन्होंने 1980 में 26 हजार रुपये पर टन कर दिया और इस कीमत को बढ़ावा

दे कर्त्तव्यसं सफर कर रहे थे। हमने उन को कहा कि इतना प्रोफिट मत कमाओ और हस में आप कुछ कमी कीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर नुकसान का सबाल नहीं है लेकिन जब उन्होंने प्रोफिट बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर दिया और हमने उन से कहा कि प्राफिट कम करो, अपनी प्राइस कम करो लेकिन आइस कम करने के लिए वे तैयार नहीं हुए जब ऐसी बात हुई तो हमने इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया और इक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। अब उन का माल, केप्रोलेक्टर्स बचा पड़ा है और बिक नहीं रहा है और हस बजह से उन के सामने मुश्किल आ रही है।

**SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:** The only thing is, the Government policy is import landed cost is much less than their product in India. Then all the material will be imported from outside the country.

**MR. SPEAKER:** No. Shri Motibhai Chaudhary.

**श्री मोती भाई शार० चौधरी :** अध्यक्ष महोदय इसने यह रखा गया है कि क्या सरकार को पता है कि गुजरात स्टेट फिल्म्स इंजिनियर कम्पनी के बन्द होने की नीबत आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस कम्पनी ने पिछले 3 सालों में कितना मुनाफा कमाया है, कितना डिस्ट्रिक्शनरी प्राइस तय कर देते हैं जिस की वजह से यह जो स्टेट अन्डरटेकिंग है, इस में यह सब घाटा होता है तो इस के माइने यह होते हैं कि आम लोगों ने विश्वास के पात्र नहीं होते। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे कोई विचार नहीं कर रही है, जिस दृंग से स्टेट अन्डरटेकिंग चलनी चाहिये, उन को दैसे चलाने के लिए क्या आप तुल सोच रहे हैं या नहीं।

**श्री शीरेन्द्र पाटिल :** आपने जो कम्पनी के बन्द होने का सबाल पूछा है उस के बारे में मुझे यह कहना है कि फिल्म्स इंजिनियर कम्पनी के बन्द होने का सबाल नहीं है। वहां पर फिल्म्स इंजिनियर तो प्रोड्यूस होता है लेकिन जो केप्रोलेक्टर्स का यनिट है उस यनिट की हालत यह ही गई है कि उन लोगों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ाने की वजह से उस की कोई मांग नहीं है। इसलिए 5 हजार टन के प्रोलेक्टर्स दैसे का लैसा ही पड़ा हुआ है। उस को लेने वाला कोई नहीं है यह हालत है लेकिन फिल्म्स इंजिनियर कम्पनी ठीक तरह से चल रही है।

**अध्यक्ष महोदय:** नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री राम विलास पासवान।

“आक्रोश” फिल्म को “ए” प्रमाण-पत्र दिया जाना

\* 840. **श्री राम विलास पासवान :** क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेंसर बोर्ड द्वारा “आक्रोश” फिल्म को “ए” (केवल व्यास्तों के लिए) प्रमाण-पत्र दिया गया है; और

(ख) यदि ही, तो उस के क्या कारण हैं?